

सदस्य की सूचना के लिए जो ऐडिशनल एलोकेशन हमने किया है वह मैं पढ़ देता हूँ :

आन्ध्र-प्रदेश—56.50 लाख, बिहार—245.50 लाख, केरल—34 लाख, उड़ीसा—20 लाख 50 हजार, तामिलनाडु 1 करोड़ 3 लाख, उत्तरप्रदेश 2 करोड़ 4 लाख, और वेस्ट बंगाल—99 लाख। तो इस तरह सात प्रदेशों को जहाँ जनसंख्या ज्यादा है यह ऐडिशनल एलोकेशन हमने किया है। . . . (व्यावधान)
. . . मध्यप्रदेश में 43 जिले हैं पहले ही जिलों की संख्या वहाँ बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने हिस्से से ज्यादा पहले ही मिल गया मध्यप्रदेश को।

श्री हुकम चन्द कछावय : माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1 हजार लोगों को साल भर में वह एक जिले में काम देंगे। तो क्या उन्होंने इस योजना को बनाते समय यह ध्यान दिया था कि एक जिले में बच्चों की पैदावार कितनी है और यह आगे जा कर कितना बैठेगा ? इस संबंध में आपने जो योजना बनाई है उसमें यह देखा है कि गांवों के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वह बेकार हैं, दूसरों के यहां काम करते हैं ? उनके लिए भूमि जो बेकार पड़ी है उसे खेती करने लायक बनाने की कोई योजना आपने बनाई है ? और बहुत से गांवों में अभी सड़कें पहुंचानी हैं, बिजली पहुंचानी है, तो सड़कों के निर्माण के लिए और बिजली पहुंचाने के लिए ऐसी कौनसी योजना आपने बनाई है ?

सध्यक्ष महोदय : इसमें बच्चों का और एरिया का सबका सबाल मिला दिया।

श्री शेर सिंह : यह योजना जो बनी है इसमें ऐसे ही काम रखे गए हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। यह काम इस ढंग के हैं, लेबर इंटेसिव काम हैं, इन में रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा, ऐसे काम हम कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ यह भी ध्यान रखा है कि काम करने के बाद कोई ऐसे-दूसरे भी

क्रियेट होने चाहिए। यह नहीं कि जैसे पहले रिलीफ के काम होते थे, मिट्टी ढाली, बारिश आई और सारी मिट्टी बह गई। अब हम यह सोच रहे हैं कि सड़क बनानी है तो पक्की बनाएं। कच्चा काम न करवाएं। पक्की सड़क बनवाएं। और भी काम जो हों वह ऐसे हैं कि जिनसे परमानेंट एसेट्स क्रियेट हों साथ-साथ ताकि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बने और उससे और ज्यादा एम्प्लायमेंट क्रियेट हो।

SHRISHYAMNANDAN MISHRA : The extent of employment is really determined by the its income content.

SHRISHER SINGH : I require notice of this question.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : The hon. Minister has mentioned the names of almost all States except Assam. I would like to know from him whether Assam has been excluded from this.

SHRISHER SINGH : No, Assam is very much in the picture. We are taking this scheme to Assam also.

Assessment of Loss of Crop in U. P. due to recent rains and Central Assistance therefore

*1450. **SHRIR. S. PANDEY :** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether *rabi* gains worth hundreds of crores of rupees have been damaged in Uttar Pradesh during the recent rains there;

(b) whether an on-the-spot assessment of this loss has been made by the Central Government and, if so, the main findings thereof; and

(c) the assistance given by the Centre to the State Government to provide relief to the affected farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASEHEB P. SHINDE) : (a) The U. P. Government has stated that heavy losses to *Rabi* crop have occurred owing to untimely rains in Uttar Pradesh.

(b) A Central Team of Officers formed by the Ministry of Finance along with the Planning Commission and other concerned Ministries recently visited the State in the first week of July, 1971 for an assessment of the situation arising out of damage to crops due to unseasonal rains in April—May, 1971 and of the requirement of funds for relief measures for purposes of Central assistance. The Report of the Team has just been received (on 26-7-71) and is under the consideration of the Government.

(c) Central assistance would be provided towards expenditure actually incurred by the State Government against the ceilings that may be adopted on the basis of the recommendations of the Team.

श्री रामसहाय पांडे : माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि रिपोर्ट अभी मिली है—कृपा कर यह भी बताने की कोशिश करें कि रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमन्, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने यह कहा है कि जो बाढ़ आई है, उससे 200 करोड़ रुपये का खेती का नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे और इस विपत्ति को दूर करने के लिये जो रिलीफ कार्यक्रम आप निर्धारित करेंगे उस पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा, कैसे खर्च होगा और कब खर्च होगा ?

SHRI ANNASAHAB P. SHINDE: The relief measures to be taken need not await either the visit of the Central team or the assistance from the Central Government, because they are the direct responsibility of the State Government, and they have to take immediate steps; if the State Government finds that it is beyond their capacity to carry out these relief measures then they have to request for a Central team, and accordingly the request was received and the Central Government team has recently visited the State and submitted its report. But the State Government has taken the necessary steps for providing relief. About 27 districts are affected very severely, and in those districts, the recovery of Government arrears and

taccavi etc. has been stayed; gratuitous relief is being provided. Rs. 25 per family was being provided, but the State Government has taken a decision to increase it to Rs. 100. A number of other steps are being taken in order to supply seeds, to give taccavi, and credit for fertilisers and other agricultural inputs.

श्री रामसहाय पांडे : अब मैं एक दूसरे सन्दर्भ में पूछना चाहता हूँ—कमी-कमी जब बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है, लेकिन जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो जमीन गीली हो जाती है और उसमें कुछ न कुछ अनाज या तरकारी—माजी या कोई अन्य फसल उगाई जा सकती है। जब आप रिलीफ का काम अपने हाथ में लेते हैं तो क्या आपका ध्यान इस ओर भी जाता है कि उस गीली जमीन में तुरन्त कुछ न कुछ बो दिया जाये, जिससे तुरन्त कोई न कोई फसल मिल जाये ताकि रिलीफ के काम के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सहायता मिल सके ?

SHRI ANNASAHAB P. SHINDE: I would like to draw the attention of the hon. Member to the fact that in the main question he is actually referring to the damage to the rabi crops, that is, before the rainy season. It has nothing to do with floods or anything like that.

SHRI R. S. PANDEY: It is a blessing in disguise. . .

अध्यक्ष महोदय : इसका ताल्लुक नहीं है।

SHRI R. S. PANDEY: Since it has something to do with agriculture, it should be taken into account. वहाँ पानी भर जाता है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। अगर इन को यह मालूम हो कि एक-दो महीने में कौनसी चीज पैदा हो सकती है, उस चीज को वहाँ पर पैदा किया जा सकता है

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल डेमेज के बारे में था . .

श्री रामसहाय पांडे : डेमेज का मतलब यह है कि सरकार सहायता कार्य शुरू करने जा

रही है। रिपोर्ट इनके पास आ गई है, सहायता कार्य से इसका भी सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री एन० एन० पांडे : यू० पी० सरकार ने कहा है कि 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान रबी-क्रॉप का हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की फिंगर्स कुछ दूसरी थीं। उसके बाद सेंट्रल टीम को वहां भेजा गया। मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल टीम का असेसमेंट क्या है तथा आप क्या-क्या सहायता यू० पी० सरकार को दे रहे हैं ताकि वहां पर रिलीफ मेजरज दिये जा सकें।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: There is no conflict between the assessments of the UP Government and the Central Government. We have been relying on the assessment of the State Government because they are close to field conditions.

As for relief measures, I have already mentioned about the team. Their report as to the extent of assistance recommended is being examined.

श्री ईश्वर चौधरी : मैं उत्तर प्रदेश के बंगाल में दो कदम आगे बढ़ कर उत्तर-बिहार के बारे में पूछना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आप आगे न बढ़िये।

श्री ईश्वर चौधरी : मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। असामयिक वर्षा के कारण इस बार जो बाढ़ आई, उससे बहुत ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं। क्या उनको खरिह-बिहन या मिश्र-मिश्र तरह की सहायता पहुंचाने की तत्काल कोई योजना है? यदि ऐसी योजना है तो उसको कब तक कार्यान्वित किया जायेगा—यह बिलकुल जनरल सवाल है?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have mentioned that relief measures are being taken by the State Government.

श्री राम सुरत प्रसाद : माननीय मंत्रीजी ने बताया कि रिलीफ-मेजरज देने की उत्तर प्रदेश

सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आर्थिक-संकट है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि रिलीफ मेजरज के लिये अब तक कोई आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार ने दी है? यदि दी है, तो कितनी? अगर नहीं दी है तो कब तक देने का इरादा है ताकि रिलीफ मेजरज वहां पर जल्दी से जल्दी चालू किये जा सकें?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We have received the report of the Central team which has recommended the quantum of assistance to be given to the State Government.

T. B. among Workers of Mica Mines in Hazaribagh

*1452. **SHRI R. P. YADAV:** Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large number of workers in mica mines in the District of Hazaribagh are suffering from Tuberculosis as the ventilation in mica mines is almost nil; and

(b) the steps being taken for regorous inspections by the Director General of Mines and Safety regarding ventilation in the mines and arrangement of drinking waters at mine-sites?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVING VERMA): (a) As Tuberculosis is not a notifiable disease under the Mines Act, 1952; statistics regarding its incidence are not available with the Director General of Mines Safety.

(b) Regular inspections are carried out by the Mines Inspectorate to enforce the statutory provisions relating to ventilation and supply of drinking water.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हजारी बाग जिले की किसी भी खान में इस तरह की कोई भी सेवा नहीं है, यहां तक कि मजदूरों के लिये तल की भी व्यवस्था नहीं है, उनकी